

[Shri Anasaheb P. Shinde]
1973. In order to make good the cut in the rice supplies, the wheat supplies were substantially increased. The monthly allotment of wheat to Kerala from January to April, 1973 was only 7000 tonnes and this was increased to 30 to 35 thousand tonnes from May onwards. Thus there was no overall reduction in the allotment of foodgrains to Kerala as a whole. The total supplies of foodgrains to Kerala during January to July, 1973 amounted to 542.9 thousand tonnes as against 497.7 thousand tonnes supplied during the corresponding period of last year.

Steps have been taken to ensure that adequate stocks are maintained with F.C.I. in Kerala

12.19 hrs.

STATEMENT BY MEMBER RE COMPANIES PRODUCING SCOOTERS AND MOPEDS

श्री सन् लिमिटेड (बांका) अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा बयान है, इस लिये पढ़ाई हुई। भारी उद्योग विभाग के उप-मंत्री श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद ने मेरे अतिरिक्त प्रश्न सं० 2625 के जवाब में 9 अगस्त, 1973 को कहा कि मैसर्स एस्कार्ट लि० को छोड़ कर स्कूटर तथा मोपेड बनाने वाली सभी कंपनियों ने अपने उत्पादन की मरुभूमत विदेशी महयोग से की है। यह बिलकुल गलत है।

क्या मंत्री महोदय इस बात को काट सकते हैं कि पूना की मैसर्स कीनेटिक इजीनियरिंग प्राइवेट लि० ने बिना विदेशी सहायोग के अपनी मोपेड की पैदावार प्रारम्भ की? कोयम्बूर की मोपेड इन्डिया लि० कम्पनी को विदेशी सहायोग का सुझा करार और तीन लाख बढ़ाये की अनुमति देने का सरकार ने जो असाधारण निर्णय किया, उस की पुष्टि में मंत्री महोदय ने यह शक्ति बखानी की।

मैं मांग करता हूँ कि मंत्री जी सही स्थिति सदन के सामने रखें और शलत बयानी के लिये खेव प्रकट करें।

भारी उद्योग विभाग में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) . भारतीय संसद महोदय, इस बात का खयाल नहीं किया जाता है कि मैसर्स कीनेटिक इजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बिना विदेशी सहायोग के मोपेडों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है। लोक सभा में 9 अगस्त, 1973 को अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2625 के भाग (ब) के उत्तर में मैसर्स कीनेटिक इजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम भूल से छूट गया है। सही उत्तर निम्नलिखित होना चाहिए —

“मैसर्स एस्कार्टस लिमिटेड और मैसर्स कीनेटिक इजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ कर सभी कम्पनियों ने विदेशी महयोग से निर्माण प्रारम्भ किया। इस समय मोपेडों का निर्माण कर रही कम्पनियों से से केवल एक कम्पनी विदेशी सहायोग कर रही है।”

इस त्रुटि के लिए खेव है।

उत्तर में यह कहा गया था कि मोपेडों का निर्माण करने वाली कम्पनियों में से एक कम्पनी विदेशी सहायोग कर रही है। यह कम्पनी मैसर्स मोपेड इन्डिया है।

इस मामले में केंद्र कारखानों से रामस्ती की घटाई नहीं अदायगी पर तीन वर्षों की अग्रतर अवधि के लिए सहायोग बढ़ाया गया है। यह एक-किसी-किसी की एक-एक के सहायोग से कुछ समय तक उत्पादन करता रहा है, जिसमें विदेशी सहायोगकर्ता की विशेष रूप से वेस्ट की हुई अन्वेषण का अतिरिक्त करण मिश्रित है। इसलिये सरकार ने तीन वर्षों की अवधि में अन्वेषण के लिए सहायोग करार को बढ़ाने की स्वीकृति दे-की है इसकी वजह यह है कि लोग

वर्षों की बढ़ाई गई अवधि के अन्दर वे अपनी गाड़ी का पूर्णरूप से देशीकरण करेंगे और तीन वर्षों की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात्-पेटेन्ट की हुई प्रक्रिया और जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए पूरा और अग्रोध अधिकार प्राप्त करेंगे ।

वैध कारण से इस वृद्धि की स्वीकृति देने पर जारी रहने वाले सहयोग के रूप में इस स्थिति में विशेषरूप से उल्लेख किया गया था । एक एकक के नाम का भूल से उल्लेख न करना, जिसका कि खेद है, इस प्रकार सहयोग की अवधि बढ़ाने के बारे में निर्णय, अथवा विदेशी सहयोग के बिना एककों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है के बारे में वक्तव्य से इसका कोई संबंध नहीं है ।

12.20 hrs.

RE. STATEMENTS LAID ON THE
TABLE

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, कल यहाँ स्टेट्स का कोटा कम करने का मामला उठाया गया था । आप ने कहा था कि मंत्री महोदय बयान देंगे । मंत्री महोदय ने कोई बयान नहीं पढ़ा है, जब कि आर्डर पेपर के हिसाब से ले करने का सवाल नहीं है, वह स्टेटमेंट देंगे ।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Aipore): All these items 18 to 22 were just laid on the Table of the House. They should actually be read in the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: And Members should be allowed to seek clarification.

MR. SPEAKER: Copies were available in the Notice Office.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I came through the Notice Office and they told me that one statement was available; the others were not there.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट्स में संकट पैदा हो गया है । अखिर गेहूँ का कोटा क्यों कम किया गया है ? मुझे पता नहीं मंत्री महोदय ने अपने बयान में क्या कहा है । मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ।
(ध्यवधान)

SHRI INDRAJIT GUPTA: Items 21 and 22, both of which concern the very serious food crisis, were laid; they should be read out here.

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है वह पढ़ दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ लिया है, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश का कोटा आधा कर दिया है । यह सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि हर स्टेट का कोटा कितना कम किया गया है । (ध्यवधान)

MR. SPEAKER: After the statements, rules do not permit questions being asked. If there is a specific question that you want to raise, sometimes in the day he can make a statement in reply.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): Rules do not permit the statements being laid on the Table of the House.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I wrote to you in the morning, when I saw the Order Paper. I wanted to raise a point of order on two items—No. 18, dealing with dearness allowance to the Central Government employees and No. 21 about the supply of wheat to U.P. I know that 216 points will be reached next month. The dearness allowance will have to be increased and you must allow us to have a discussion. I know that they have given only Rs. 7, 8 or 10. (Interruptions)